

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
न्याय विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 984  
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

**सर्वोच्च न्यायालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग**

**984. श्रीमती पूनमबैन माडम :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों के प्रबंधन और निर्णय लेने में सहायता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ;

(ग) एसयूपीएसीई (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी) जैसे एआई-संचालित उपकरणों की तैनाती की स्थिति क्या है ; और

(घ) गुजरात राज्य में जिलावार कितने ई-न्यायालय कार्यरत हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);  
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ख) :** भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन अधिगम (एमएल) आधारित साधनों को मामला प्रबंधन में परिनियोजित किया जा रहा है। इन साधनों का प्रयोग सांविधानिक न्यायपीठ के मामलों में मौखिक दलीलों का लिप्यन्तरण करने में प्रयोग किया जा रहा है। कृत्रिम मेधा सहायता प्राप्त लिप्यन्तरित वकीलों को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के साथ निकट समन्वय करके एआई और एमएल आधारित साधनों का प्रयोग अंग्रेजी भाषा से निर्णयों का 18 भारतीय भाषाओं अर्थात् - असमिया, बंगला, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, कॉकणी, मलयाली, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, में अनुवाद करने में भी प्रयोग कर रहा है। इन निर्णयों को भारत के उच्चतम न्यायालय के ईएससीआर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने आई आई टी मद्रास के निकट

समन्वय से, त्रुटियों की पहचान के लिए इलैक्ट्रानिक फाइलिंग साफ्टवेयर के साथ एकीकृत एआई और एमएल आधारित साधनों को परिनियोजित किया है। हाल ही में प्रोटोटाइप की पहुंच को दो सौ अभिलेख पर अधिवक्ताओं को प्रदान किया गया है।

भारत के उच्चतम न्यायालय आईआईटी मद्रास के सहयोग से त्रुटियों, डाटा, मेटा डाटा निष्कर्षण को संसाधित करने के लिए, एआई और एमएल के प्रोटोटाइप का भी परीक्षण कर रहा है। यह साधन आधारित एआई और एमएल इलैक्ट्रानिक फाइलिंग मॉड्यूल और मामला साफ्टवेयर अर्थात् एकीकृत मामला प्रबंधन और सूचना पद्धति (आईसीएमआईसी) के साथ एकीकृत किया जाएगा।

तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी साधन आधारित एआई और एमएल का प्रयोग विनिश्चय निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं।

(ग) : एआई आधारित साधन न्यायालय दक्षता में उच्चतम न्यायालय पोर्टल सहायता (एसयूपीएसी), का उद्देश्य मामलों की पहचान करने के अलावा पूर्व उदाहरणों की मेधावी शोध के साथ मामलों के वास्तविक मेट्रिक्स को समझाने के लिए एक मॉड्यूल विकसित करना है, यह विकास की एक प्रयोगात्मक-प्रक्रम है। एसयूपीएसीई को ग्राफिक प्रसंस्करण यूनिट (यूनिटों) तथा टेंसर प्रसंस्करण यूनिट जैसी अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकी आधारित यूनिटों के उपापन और परिनियोजन के पश्चात परिनियोजित किया जा सकेगा।

(घ) : गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाओं का प्रयोग करते हुए अनिवार्य ई-फाइलिंग और सुदूर न्यायनिर्णयन अहमदाबाद शहर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों की अधिकारिता के लिए बैंकों और गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा संस्थित किए जा रहे प्रक्राम्य लिखत (एनआई) अधिनियम, 1881 के अधीन चैकों के अनादर के मामले से निपटने के लिए प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त गुजरात सरकार ने अहमदाबाद शहर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के प्रक्राम्य लिखत अधिनियम, के सभी ई-फाइल किए गए मामलों पर सुदूर न्यायनिर्णयन के माध्यम से विचार करने के लिए राज्य के सभी दंडाधिकारिय न्यायालयों की अधिकारिता विस्तारित की है। तदनुसार, अधिसूचना के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद शहर के ई-फाइल किए गए मामलों के लिए सुदूर न्यायनिर्णयन प्रणाली तक राजसवार पहुंच (एसएआरएएस) संख्या 1 न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में अहमदाबाद, आणंद, नर्मदा और गिर, सोमनाथ में तैनात पांच न्यायिक अधिकारियों को नामनिर्देशित किया है। इन न्यायिक अधिकारियों का कार्य स्थान इन सुदूर न्यायनिर्णयन अधिकारियों पर अध्यक्षता करने के लिए नहीं बदला जाएगा।

इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय परियोजना के तत्वाधान में वर्चुअल यातायात न्यायालय को कार्यान्वित किया गया है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	ज़िला	वर्चुअल यातायात न्यायालयों की संख्या
1	नवसारो	3
2	पचमहल	1
3	भावनगर	1
4	दाहोद	2
5	पोरबदर	1
6	तापी	1
7	अमरेली	3
8	गिर सोमनाथ	1
9	सुरेंद्रनगर	1
10	बनासकाठा	2
11	साबरकाठा	1
12	अहमदाबाद शहर	1
13	अहमदाबाद ग्रामीण	1
14	जूनागढ़	1
15	पाटन	1
<b>कुल</b>		<b>21</b>

\*\*\*\*\*